भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1160
जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

वित्तीय समावेशन

1160. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और ग्रामीण जिलों में वित्तीय सारक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के कटनी, पन्ना और खजुराहो में कितने नए पीएमजेडीवाई खाते खोले गए, कितने रुपे कार्ड जारी किए गए और कितने बीमा/पेंशन कवर दिए गए हैं;

(ग) खातों के उपयोग और ऋण/बीमा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर चलाए गए वित्तीय साक्षरता अभियानों और शिकायत निवारण तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि इस संबंध में संख्या कम है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त जिलों में असुरक्षित परिवारों के लिए औपचारिक बैंकिंग, सूक्ष्म-ऋण और सामाजिक-सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): सरकार ने अगस्त, 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत की और "बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क" को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कीं।

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ढांचा डीबीटी प्रवाह को आसान बनाने, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं को अपनाने, ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने आदि जैसे उपायों के लिए आवश्यक आधार प्रदान कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के कटनी, पन्ना और खजुराहो में खोले गए नए पीएमजेडीवाई खाते, रुपे कार्ड और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के माध्यम से बढ़ाए गए बीमा/पेंशन कवर की संख्या अनुबंध में दी गई है।

सरकार का यह प्रयास रहा है कि समाज के सभी वर्गों की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हो। विभिन्न वित्तीय साक्षरता उपाय किए जा रहे हैं जिनमें, अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना की शुरुआत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिये समुदाय के नेतृत्व वाले नवाचार और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से की गई है। देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

ii. बैंक अपने एफएलसी के जरिए यूपीआई के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" और *99# (यूएसएसडी) पर आम जनता के लिए शिविर और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए अनुकूलित शिविर का आयोजन करता है।

iii. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संदेशों को कवर करते हुए प्रतिमाह एक शिविर आयोजित करें जो वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका का भाग है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल हैं।

iv. देश भर में आम जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए वर्ष 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित किया जाता है।

v. "आरबीआई कहता है" नामक आरबीआई का मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

शिकायत निवारण तंत्र के लिए, प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु संगठन में उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। यदि आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर नहीं दिया जाता है, तो ग्राहक "रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021" से संपर्क कर सकता है जो शिकायतों का निःशुल्क निवारण प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पीएमजेडीवाई खाते खोलना, पीएमजेडीवाई खातों के लिए केवाईसी का पुनः सत्यापन, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई योजनाओं में नामांकन शामिल हैं। हाल ही में देश भर में दिनांक 01.07.2025 से 31.10.2025 तक 4 महीने का ग्राम पंचायत संतृप्ति अभियान आयोजित किया गया था।

*****

"वित्तीय समावेशन" विषय पर दिनांक 08.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

जिले का नाम	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)							
	मार्च'23 तक की स्थिति के अनुसार		मार्च'24 तक की स्थिति के अनुसार		मार्च'25 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 19.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार	
	कुल पीएमजेडीवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों को रुपे कार्ड जारी किए गए	कुल पीएमजेडीवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों को रुपे कार्ड जारी किए गए	कुल पीएमजेडीवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों को रुपे कार्ड जारी किए गए	कुल पीएमजेडीवाई खाते	पीएमजेडीवाई खातों को रुपे कार्ड जारी किए गए
कटनी	5,56,761	4,23,062	6,22,763	4,63,655	6,54,312	4,84,920	6,91,538	5,11,804
पन्ना	5,64,247	3,78,840	6,10,861	4,06,407	6,49,592	4,27,704	6,69,197	4,39,199
खजुराहो	10,45,963	8,29,592	11,32,688	8,88,169	12,07,102	9,35,545	12,44,118	9,67,113
स्रोत: बैंक								

जिले का नाम	**जनसुरक्षा योजनाओं में नामांकन**							
	मार्च'23 तक की स्थिति के अनुसार		मार्च'24 तक की स्थिति के अनुसार		मार्च'25 तक की स्थिति के अनुसार		26.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार	
	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई
कटनी	1,70,005	3,53,485	2,25,533	5,10,399	2,66,382	5,95,703	2,90,653	6,39,257
पन्ना	73,856	3,17,803	1,19,346	4,29,312	1,64,192	4,92,863	1,83,201	5,21,274
खजुराहो	1,82,775	4,87,622	2,81,195	7,87,994	3,60,875	9,25,568	3,95,293	9,81,458
स्रोत: बैंक और बीमा कंपनियां								

जिले का नाम	**एपीवाई अभिदाता**			
	मार्च' 23 तक की स्थिति के अनुसार	मार्च' 24 तक की स्थिति के अनुसार	मार्च'25 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.10.25 तक की स्थिति के अनुसार
कटनी	54,938	66,950	79,897	87,030
पन्ना	49,938	66,482	81,792	88,871
खजुराहो	97,452	1,22,745	1,43,653	1,57,465
स्रोत: पीएफआरडीए				